दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इंजीनियर

2089. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कितने इंजीनियर कार्यरत हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंध रखने वाले इंजीनियरों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) दिल्ली विकास राधिकरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों हेतु आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रभावी कदम उठाये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत इंजीनियरों और उनमें से श्रेणी-वार अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति से सम्बन्धित इंजीनियरों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि डी०डी०ए० के इंजीनियरिंग विभाग में नियुक्ति विनियमों के तहत जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर की जाती है। रिक्त पदों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय से कोई नियुक्ति नहीं की गयी। तथापि, नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के लिए सुरक्षित केवल इनसे ही सम्बन्धित अभ्यार्थियों द्वारा भरे जाते है।

विवरण

विषय : डी० डी० ए० में कार्यरत इंजीनियरों की श्रेणीवार स्थिति

क्र० सं०	श्रेणी का नाम	कुल कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति	अनुसूचित जाति के कुल कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति	अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के कुल कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति
1.	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	1447	113	शून्य
2.	जूनियर इंजीनियर (वि०/यां०)	189	19	शून्य
3.	सहायक इंजीनियर (सिविल)	510	72	03
4.	सहायक इंजीनियर (वि०/यां०)	69	08	शून्य
5.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	127	10	01
6.	कार्यपालक इंजीनियर (वि०/यां०)	17	02	शून्य
7.	अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	32	शून्य	शून्य
8.	अधीक्षक इंजीनियर (वि०/यां०)	03	शून्य	शून्य
9.	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	05	शून्य	शून्य
10.	मुख्य इंजीनियर (वि०/यां०)	01	शून्य	शून्य
	योग:	2400	224	04

Rural Landless Employment Guarantee Programme in Maharashtra

2090. MISS SAROJ KHAPARADE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Rural Landless Employment Guarantee Programme is a part of the Jawahar Rozgar Yojana (JRY);

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any targets for creating employment opportunities for the rural landless in Maharashtra were fixed during the last three years;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether those targets were achieved; and

(f) if not, the remedial measures